

VI. मूल्य की स्थिति

2012-13 के दौरान अब तक थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगभग 7.5 प्रतिशत पर रही है। यह स्थिति कई कारकों के मिलेजुले असर को दर्शाती है: राजकोषीय असंतुलन के असर का विस्तार, पूर्व के विनिमय दर के अवमूल्यन के असर का अंतरण और आपूर्ति की कमजोर स्थिति। वृद्धि दर में गिरावट आने के बावजूद खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति के रहने का विषय एक चिंता के रूप में उभरा है। मानसून के देरी से आगमन से जहां सब्जी जैसी वस्तुओं ने मूल्य के दबावों को कम करने में मदद की वहीं खरीफ फसलों की संभावित कमी से खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से अनाजों, दलहनों तथा तिलहनों के मूल्यों में बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है। यद्यपि सितंबर 2012 में नियंत्रित मूल्यों में किए गए संशोधन से अल्पावधि में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी, परंतु राजकोषीय घाटे में कमी आने के चलते मध्यावधि में मुद्रास्फीति दबावों में कमी आएगी। यदि कच्चे तेल की कीमतें एक दायरे में रहती हैं तथा रुपये में मजबूती का रुख हो तो ईंधन जनित मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आ सकती है। समग्र रूप में, अल्पावधि में मुद्रास्फीति की गति के असहज स्तर पर बने रहने की संभावना है, बशर्ते आपूर्ति संबंधी प्रमुख आघात जैसी स्थिति न हो।

वैश्विक मुद्रास्फीति की स्थिति सहज होने पर भी भारत की स्थिति भिन्न

VI.1 कमजोर मांग के साथ-साथ मामूली वृद्धि दर, उच्च बेरोजगारी तथा ऋणात्मक उत्पादन अंतर के चलते उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के माहौल में सहजता आई। ओईसीडी देशों की औसत मुद्रास्फीति जनवरी 2012 के 2.8 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2012 में 2.0 प्रतिशत हो गई। परंतु अधिकांश उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति की उच्च दर के साथ भारत की स्थिति भिन्न रही जो ढांचागत तथा देश विशिष्ट कारकों की भूमिका दर्शाती है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा और मात्रात्मक सहूलियत दिए जाने से वैश्विक चलनिधि में वृद्धि

VI.2 अधिकांश उन्नत देशों की मौद्रिक नीति का रुझान वृद्धि की बहाली को ध्यान में रखते हुए समर्थनकारी रहा (सारणी VI.1)। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा हाल में तथा विशेष रूप से यूरोपीय केंद्रीय बैंक, अमरीका के फेडरल रिजर्व तथा बैंक ऑफ जापान द्वारा सितंबर 2012 में अपनाई गई मौद्रिक नीति के नरम रुख ने वित्तीय बाजार के दबाव को अस्थायी रूप में कम किया है

तथा इस क्रम में धारणा में सुधार के चलते आस्तियों, विशेष रूप से इक्विटी बाजारों में मूल्यों में वृद्धि हुई है (विस्तृत विवरण हेतु अध्याय V देखें)। यूएस फेड तथा बैंक ऑफ जापान द्वारा अत्यधिक सहज मौद्रिक नीति अपनायी जाने से डॉलर तथा येन में कमजोरी आने की संभावना है जिससे उभरती तथा विकासशील देशों की मुद्राओं में मजबूती आ सकती है। विनिमय दर के अंतरण प्रभाव के चलते उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। परंतु, ब्याज दरों में अंतर के चलते उन्नत अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में उपलब्ध चलनिधि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आ सकती है जिसके कारण मांग में बढ़ोतरी होने से पण्यों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

VI.3 अमरीका तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता, वेतन संबंधी कम दबाव तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीति पर पण्य की कीमतों के सीमित असर को देखते हुए अल्पावधि में मुद्रास्फीति पर दबाव कम रह सकता है। परंतु मध्यावधि में मुद्रास्फीति पर चलनिधि की उपलब्धता तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पण्य बाजारों के वित्तीयकरण के चलते मात्रात्मक सहूलियत से पण्य की कीमतों पर पड़ने वाला असर भी मुद्रास्फीति के लिए जोखिम का स्रोत बन सकता है।

अनिश्चित संभावना के चलते वैश्विक पण्य कीमतें अस्थिर रहें

VI.4 2012-13 की पहली तिमाही में पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने के बाद स्थिति बदल गई और दूसरी तिमाही में पण्यों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई (चार्ट VI.1क)। हाल के महीनों में पण्यों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह कच्चे तेल तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी की वजह से थी। परंतु, उन्नत तथा उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मांग की कमजोर स्थिति के चलते फरवरी 2012 से धातुओं की कीमतों में, हाल की अवधि को छोड़कर, गिरावट जारी रही। वृद्धि दर में आई गिरावट तथा ओपेक के देशों, ब्राजील, कजाकिस्तान तथा रूस में तेल के उत्पादन में संभावित वृद्धि एवं अमरीका में ऊर्जा की आपूर्ति में शेल गैस के असर को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल की कीमतें निश्चित दायरे में रहने की संभावना है। परंतु, ऊर्जा की कीमतों की मध्यावधि का मार्ग मध्य-पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति तय करेगी।

VI.5 कई देशों में आपूर्ति में बाधाएं आने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों, विशेष रूप से मोटे अनाजों की कीमतों में हाल के महीनों में वृद्धि हुई (चार्ट VII.1ख)। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन का

सारणी VI.1: वैश्विक मुद्रास्फीति संकेतक

देश/क्षेत्र	प्रमुख नीति दर	नीति दर (25 अक्टूबर, 2012 को)	नीति दर में परिवर्तन (आधार अंक)		सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	
			सितंबर 2009 से दिसंबर 2011	जनवरी 2012 से अक्टूबर 2012 (25 अक्टूबर को)	सित- 11	सित- 12
1	2	3	4	5	6	7
विकसित अर्थव्यवस्थाएं						
आस्ट्रेलिया	नकदी दर	3.25 (अक्तू. 3, 2012)	125	(-) 100	3.4#	2.0#
कनाडा	ओवरनाइट दर	1.00 (सितं. 8, 2010)	75	0	3.2	1.2
यूरो क्षेत्र	प्रमुख पुनर्वित्त परिचालनों पर ब्याज दर	0.75 (जुला. 11, 2012)	0	(-) 25	3.0	2.6
इजराइल	प्रमुख दर (की रेट)	2.25 (जुला. 1, 2012)	225	(-) 50	2.9	2.1
जापान	गैर-संपार्श्वीकृत ओवरनाइट मांग दर	0.0 to 0.10* (अक्तू. 5, 2010)	(-) 10	0	0.2\$	-0.4\$
कोरिया	आधार दर	2.75 (अक्तू. 11, 2012)	125	(-) 50	3.8	2.0
यूके	आधिकारिक बैंक दर	0.50 (मार्च 5, 2009)	0	0	5.2	2.2
यूएस	फेडरल फंड दर	0.0 to 0.25* (दिसं. 16, 2008)	0	0	3.9	2.0
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
ब्राज़ील	सेलिक दर	7.25 (अक्तू. 11, 2012)	225	(-) 375	7.3	5.3
चीन	बैंचमार्क 1-वर्षीय जमाराशि दर	3.00 (जुला. 6, 2012)	125	(-) 50	6.1	1.9
	बैंचमार्क 1-वर्षीय उधार दर	6.00 (जुला. 6, 2012)	125 (600)	(-) 56 (-) 150		
भारत	रिपो दर	8.00 (अप्रै. 17, 2012)	375 (100)	(-) 50 (-150)	9.0\$	10.3\$
इंडोनेशिया	बीआई दर	5.75 (फर 9, 2012)	(-) 50	(-) 25	4.6	4.3
फिलीपीन्स	रिवर्स पुनर्खरीद दर	3.75 (जुला. 26, 2012)	50	(-) 75	4.7	3.6
	पुनर्खरीद दर	5.75 (जुला. 26, 2012)	50	(-) 75		
रूस	पुनर्वित्तीयन दर	8.25 (सितं. 14, 2012)	(-) 275	25	7.2	6.6
दक्षिण अफ्रीका	रिपो दर	5.00 (जुला. 20, 2012)	(-) 150	(-) 50	5.7	5.5
थाईलैंड	1 दिवसीय पुनर्खरीद दर	2.75 (अक्तू. 17, 2012)	200	(-) 50	4.0	3.4

*: लक्षित दायरे के न्यूनतम बिंदु से परिवर्तन की गणना की गयी।

#: ति.3 (जुला-सितं)

\$: अगस्त

टिप्पणी: स्तंभ (3) के कोष्ठकों के आंकड़े वे तारीख हैं, जब पिछली बार नीति दरों में संशोधन किया गया था।

स्तंभ (4) और (5) के कोष्ठकों के आंकड़े अवधि के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात में घट-बढ़ दर्शाते हैं। भारत के मुद्रास्फीति के आंकड़े औद्योगिक कामगारों के सीपीआई के हैं।

स्रोत: संबंधित केन्द्रीय बैंकों / सांख्यिकीय संस्थाओं की वेबसाइटें।

अनुमान है कि पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 2012 में अनाज के वैश्विक उत्पादन में 2.6 प्रतिशत की कमी आएगी, परंतु उनका यह विचार है कि खाद्यान्नों आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर किसी गंभीर कमी की स्थिति नहीं है। 2013 में फसलों की बेहतर स्थिति के पूर्वसंकेतों के बावजूद अल्पावधि में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न कीमतों का काफी दबाव बना हुआ है और ऐसी स्थिति में वे देश मुद्रास्फीति के स्रोत बन सकते हैं जो खाद्यान्नों के निवल आयातकर्ता हैं।

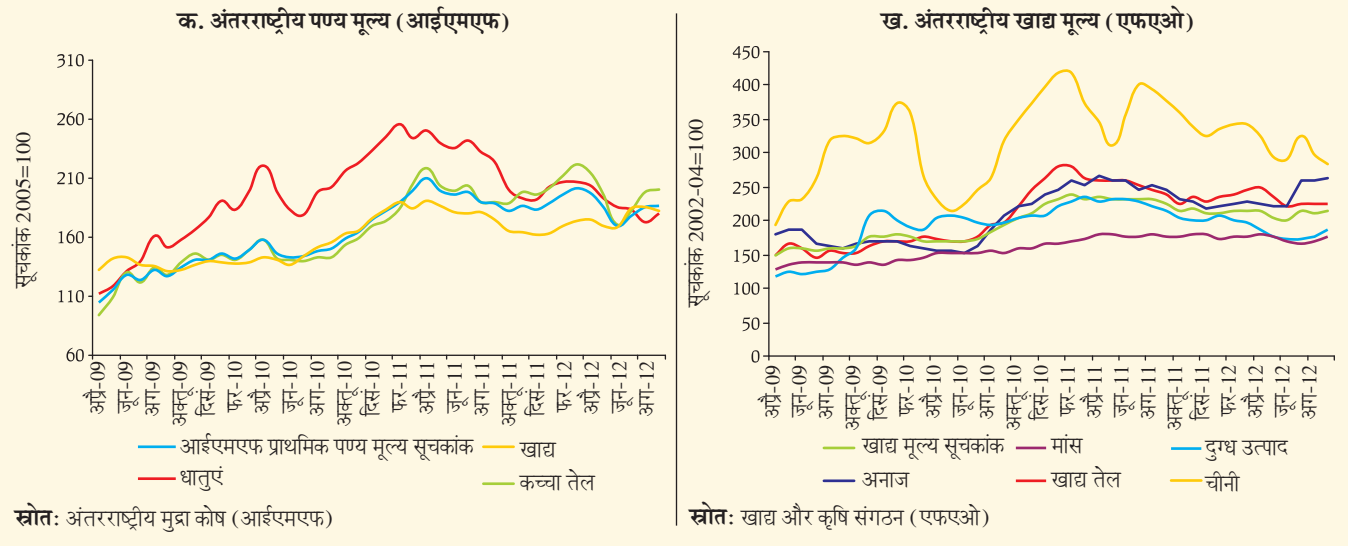
वृद्धि की गति में कमी आने के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है

VI.6 पूरे चालू वित्तीय वर्ष में हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) लगभग 7.5 प्रतिशत के आसपास बनी रही (सितंबर 2012 में अनंतिम 7.8 प्रतिशत)। जैसा कि सूचकांक

में हुई निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है कीमतों के दबावों में निरंतर वृद्धि हो रही है (चार्ट VI.2)। मूल्यों में वृद्धि की गति, जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन के मौसम समायोजित तीन महीने के चल औसत से स्पष्ट है, भी हाल के महीनों में मूल्यों में हुई कुछ वृद्धि का संकेत करती है (चार्ट VI.2घ)।

VI.7 हाल की अवधि में नियंत्रित मूल्यों में किये गये परिवर्तन मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक रहे हैं (चार्ट VI.3)। जनवरी 2012 में कोयले की कीमतों में तथा जून 2012 में बिजली की कीमतों में किए गए संशोधनों से मुद्रास्फीति बढ़ी है। डीजल तथा एलपीजी के मूल्यों में किए गए संशोधनों से वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, परंतु राजकोषीय समेकन के कारण मध्यावधि में मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आएगी।

चार्ट VI.1: वैश्विक पण्य मूल्यों की प्रवृत्ति

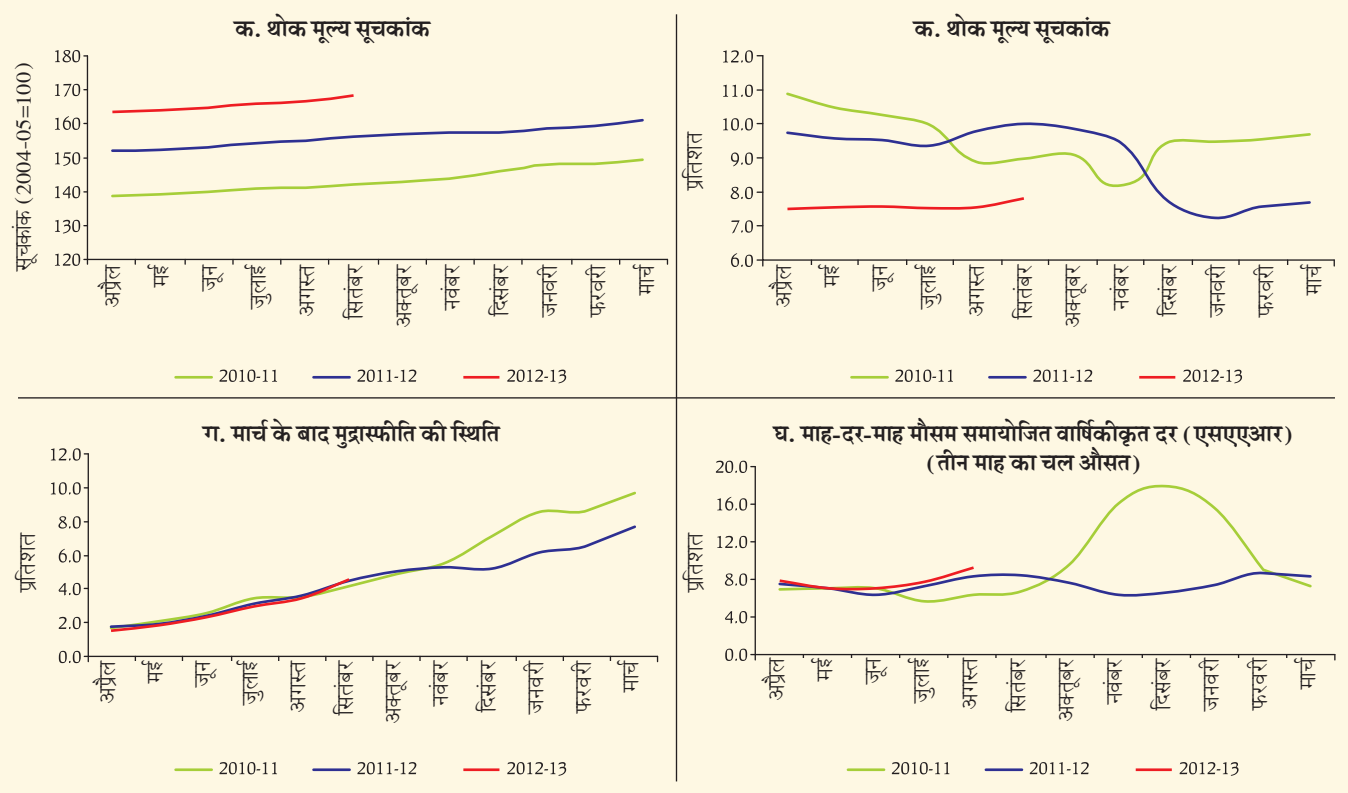


खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है जो आपूर्ति के कमजोर लोच को दर्शाती है

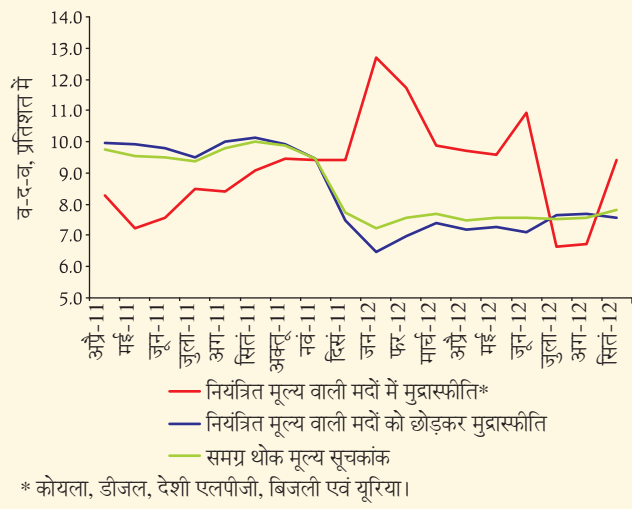
VI.8 खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। यद्यपि मानसून के आगमन में देरी के चलते फलों तथा सब्जियों की

मुद्रास्फीति में हाल के महीनों में कुछ गिरावट आई है, फिर भी प्राथमिक खाद्य वस्तु समूह में ऐसी कई मदे हैं जिनमें मूल्य संबंधी दबाव काफी है (चार्ट VI.4क)। अनाजों से संबंधित मुद्रास्फीति दो वर्ष बाद दहाई के अंकों में पहुंच गई, जबकि दलहनों की मुद्रास्फीति जून 2012 से 20

चार्ट VI.2 : शोक मूल्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां



चार्ट VI.3: भारत में नियंत्रित एवं अनियंत्रित मूल्य मुद्रास्फीति



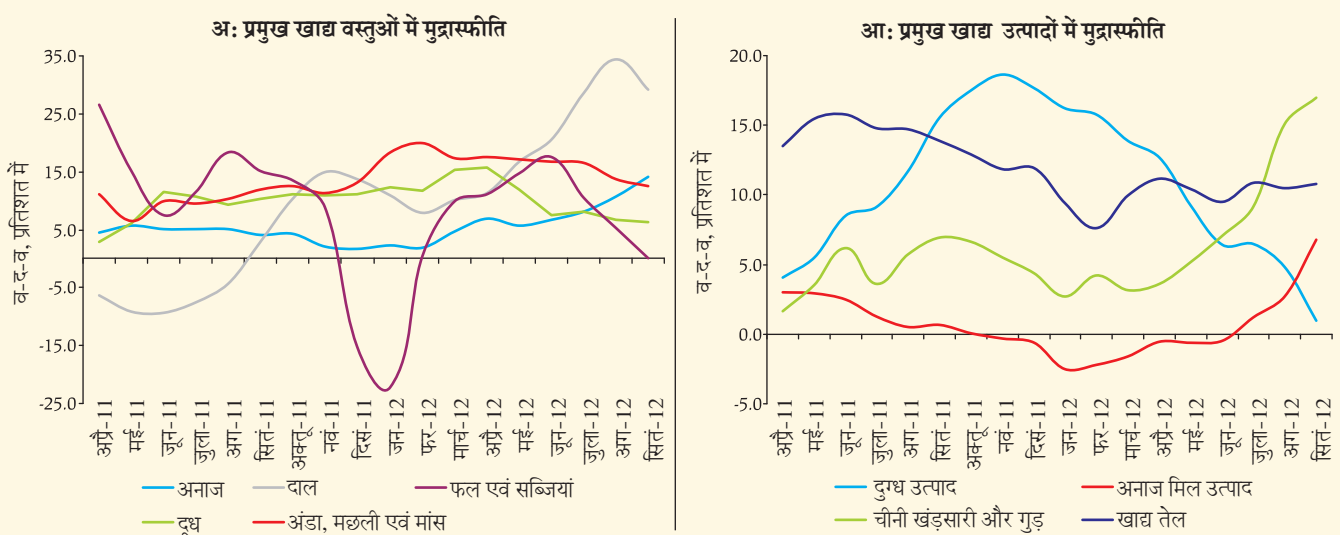
प्रतिशत से अधिक रही। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के अलावा चीनी तथा खाद्य तेल जैसे कुछ विनिर्मित खाद्य उत्पादों की कीमतों में काफी दबाव रहा (चार्ट VI.4ख)। जून तथा जुलाई 2012 के दौरान मानसून की वर्षा में आई कमी ने प्रमुख खाद्य उत्पादों की फसलों को प्रभावित किया जिसके चलते इनकी कीमतों में वृद्धि हुई (चार्ट VI.5)।

VI.9 2008-09 से औसत खाद्य मुद्रास्फीति 10.3 प्रतिशत रही जो 7.6 प्रतिशत के समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति से काफी अधिक है। संभवतः आपूर्ति तथा मांग पक्षीय दोनों ही कारकों ने खाद्य

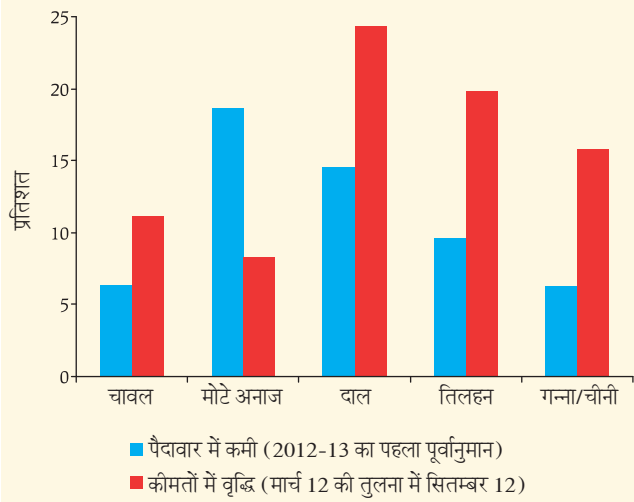
मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर रखने में भूमिका अदा की। हाल के वर्षों में ग्रामीण मजदूरी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने उत्पादन लागत को बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई जबकि उत्पादकता में वृद्धि की दर कम रही। इसके कारण अधिकांश अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साथ ही, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरी में हुई वृद्धि ने खाद्य वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी की, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजदूरी अर्जित करने वाले लोगों की कुल खपत में खाद्य वस्तुओं की मदे आबादी के अन्य खंडों की तुलना में अधिक होती है।

VI.10 घरेलू खपत व्यय संबंधी एनएसएसओ के 68वें दौर के सर्वेक्षण के हाल में जारी किए गए प्रमुख परिणाम दर्शाते हैं कि 2008-09 से 2011-12 के दौरान वास्तविक प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक खपत व्यय में वृद्धि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 6.7 प्रतिशत रही जबकि 2004-05 से 2009-10 के दौरान यह क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 2.4 प्रतिशत रही। यद्यपि यह परिणाम इस बात से भी प्रभावित हो सकता है कि 2009-10 का वर्ष सूखे से प्रभावित था जिसके कारण खपत को कम आंका गया हो सकता है और तुलनात्मक आधार नीचा रह सकता है। फिर भी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के दौरान वास्तविक खपत व्यय में हुई वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि मांग की स्थिति सुदृढ़ रही जबकि आपूर्ति का लोच कम रहने के साथ मांग में बढ़ोतरी हुई।

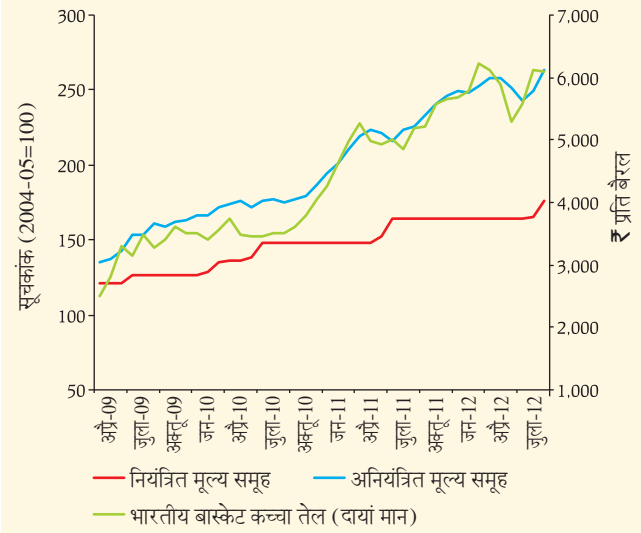
चार्ट VI.4: खाद्यान्न मुद्रास्फीति रुझान



चार्ट VI.5: प्रमुख खाद्य वस्तुओं की पैदावार एवं कीमत संबंधी रुझान



चार्ट VI.6: ईंधन की वैश्विक एवं देशी कीमतें



ईंधन की मुद्रास्फीति विलंबित अंतरण दर्शाती है: कम वसूलियां उच्च स्तर पर बनी हुई हैं

VI.11 ईंधन तथा उर्जा समूह की मुद्रास्फीति फरवरी 2010 से दहाई के अंकों में रही, केवल जुलाई तथा अगस्त 2012 इसके अपवाद रहे। सितंबर 2012 में ईंधन की मुद्रास्फीति के बढ़ने का कारण डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाना तथा मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होना था। जून 2012 से बिजली की कीमतों में की गई बढ़ोतरी ने भी इस खंड में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया।

VI.12 मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित होनेवाले उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप रहीं, जबकि ईंधन की नियंत्रित कीमतों में जून 2011 से अगस्त 2012 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया (चार्ट VI.6)। इसके चलते कम वसूली की राशि अप्रैल-सितंबर 2012 के दौरान काफी बढ़कर 856 बिलियन रुपये तक हो गई, जिसमें से लगभग 62 प्रतिशत कम वसूली की राशि डीजल के कारण थी।

VI.13 इस पृष्ठभूमि में सितंबर 2012 में सरकार ने डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर (वैट को छोड़कर) की बढ़ोतरी की तथा सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम) की संख्या प्रति ग्राहक प्रति वर्ष अधिकतम छह निर्धारित की। यद्यपि इस संशोधन के चलते ईंधन मुद्रास्फीति में आगामी महिनों में बढ़ोतरी हो सकती है, फिर भी राजकोषीय समेकन को मदद मिलने के कारण इससे मध्यावधि में मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

VI.14 तेल की कीमतों में हाल में किये गये संशोधनों के बावजूद अंतरण प्रभाव के असंपूर्ण रहने के कारण इसका असर सब्सिडियों तथा

राजकोषीय घाटे पर पड़ा (विस्तृत विवरण हेतु अध्याय II देखें)। वर्तमान में (16 अक्टूबर 2012 से) घरेलू तेल विपणन कंपनियों की कम वसूली की अनुमानित राशि डीजल के मामले में 9.8 रुपये प्रति लीटर, पीडीएस के मामले में 33.9 रुपये प्रति लीटर तथा सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी के मामले में 468.5 रुपये प्रति सिलेंडर है।

VI.15 वैश्विक कीमतें तथा विनिमय दरों की प्रवृत्तियां घरेलू ईंधनों की कीमतों पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव डालती हैं, यहाँ तक की भारत की तेल की खपत का 85 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा आयातों के जरिए पूरा होता है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमत (भारतीय बास्केट) 2011-12 के दौरान औसतन 112 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी जो 2012-13 (सितंबर तक) के दौरान 4.3 प्रतिशत घटकर 107 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गयी। यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों में मार्च 2012 से कमी आयी, फिर भी रुपये के अवमूल्यन के चलते इस अनुकूल स्थिति का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया (सारणी VI.2)।

सारणी VI.2: तेल की कीमत और विनिमय दर की तुलनात्मक स्थिति

1	सितं - 11	मार्च - 12	सितं - 12	परिवर्तन, प्रतिशत में	
	2	3	4	व-व-व	मार्च 2012 से
कच्चा तेल-भारतीय बास्केट (अमरीकी डॉलर प्रति बैरल)	108.8	123.6	111.8	2.7	-9.6
विनिमय दर (₹/ डॉलर)	47.6	50.3	54.6	-12.8*	-7.9*
कच्चा तेल- भारतीय बास्केट (₹ प्रति बैरल)	5181.9	6220.1	6104.3	17.8	-1.9

* डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएस)

VI.16 सितंबर 2012 के उत्तरार्ध से रुपये में स्थिरता आने के चलते मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित ईंधन उत्पादों की कीमतों में अक्टूबर 2012 से कुछ कमी आयी क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें दायरे के अंदर रहीं। यदि कच्चे तेल की कीमतें निश्चित दायरे में रहती हैं और रुपये में मजबूती आती है तो ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति का दबाव कम हो सकता है।

VI.17 बिजली की कीमतों में की गई वृद्धि से निविष्टि लागत संबंधी दबाव और बढ़ सकता है। सरकार द्वारा काफी कोयला ब्लॉकों के रद्द किये जाने के बाद कोयले की आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता मूल्य संबंधी दबाव का स्रोत बन सकती है, यदि कमी की पूर्ति आयातों द्वारा पूरी नहीं की जाती है। बिजली की कीमतों में संशोधन का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते अधिक ग्रीड पॉवर मिलने से बिजली के लिए जेनरेटरों पर निर्भरता कम हो जायेगी जिससे संभवतः उत्पादकों की समग्र बिजली लागत में कमी आयेगी।

मुद्रास्फीति दबावों का व्यापक असर बरकरार

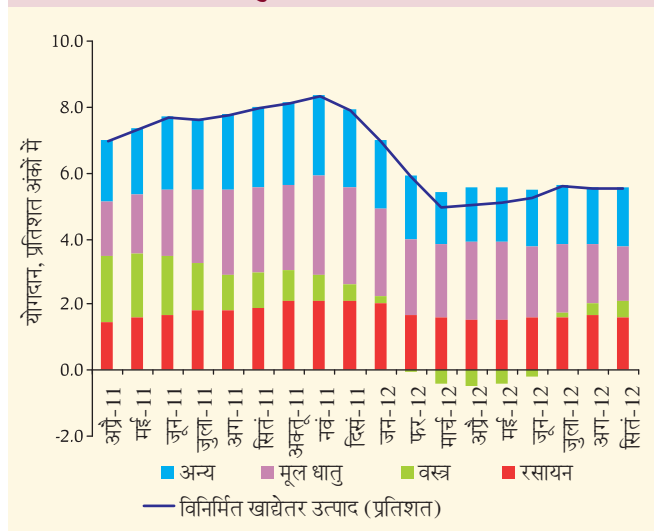
VI.18 खाद्येतर विनिर्मित मुद्रास्फीति, जो व्यापक मुद्रास्फीति दबावों का संकेतक है, 2011-12 में 5 प्रतिशत (सितंबर 2012 तक 5.6 प्रतिशत) से अधिक रही। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की थोक मूल्य मुद्रास्फीति में माह-दर-माह मौसम समायोजित वार्षिकीकृत परिवर्तन (तीन माह का चल औसत) सुदृढ़ बना हुआ है, हालांकि अद्यतन माह में इसमें कुछ कमी आयी है।

VI.19 खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों के बीच ठमूल धातु तथा धातु उत्पाद तथा रसायन समूह मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक रहे (चार्ट VI.7)। यह देखा गया कि खाद्येतर विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति में इन उत्पाद समूहों का योगदान उनके भार की तुलना में काफी अधिक रहा है। इस खंड में हाल में मुद्रास्फीति में जो वृद्धि हुई वह भी टेक्सटाइल समूह के योगदान में बढ़ोतरी होने के कारण थी जो खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में गिरावट की अवधि में काफी घटकर ऋणात्मक दायरे में आ गया था।

कुछ मदों की मुद्रास्फीति मूल मुद्रास्फीति को काफी अधिक बढ़ा देती है

VI.20 खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की कीमतों की वृद्धि में कुछ वस्तु विशेष का योगदान भी असमान रहा है। कुछ मदें मुख्यतः स्वर्ण और

चार्ट VI.7: खाद्येतर विनिर्माण उत्पाद मुद्रास्फीति: प्रमुख योगदानकर्ता

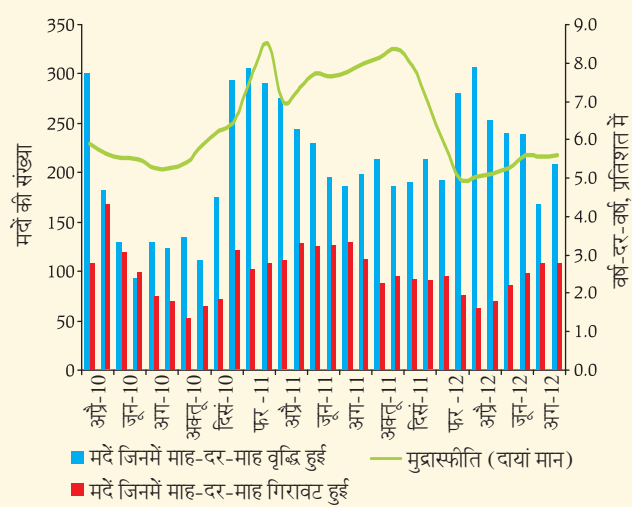


गहने, एमोनियम फॉस्फैट तथा ग्रे सीमेंट खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी ने असमानुपातिक रूप में योगदान दे रही हैं। खाद्येतर विनिर्मित सूचकांक में बदलाव से उत्पन्न सामान्य मूल्य दबावों का आकलन करते समय ऐसे असमानुपातिक प्रभावों को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

मूल्य समायोजन उच्च स्तर पर बना रहा

VI.21 विनिर्मित खाद्येतर उत्पाद मुद्रास्फीति 2012-13 के दौरान अब तक ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जिस अवधि में विनिर्मित खाद्येतर उत्पाद मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर थी उस अवधि में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली मदों की संख्या कीमतों में गिरावट आने वाली मदों की तुलना में अधिक थी। आर्थिक गिरावट के दौर में ऐसी प्रवृत्ति संबंधित मूल्यों के समायोजन के प्रति कड़ा रुख दर्शाती है जिसमें मांग संबंधी दबाव में कमी आने के बावजूद मूल मुद्रास्फीति बढ़ती है। परंतु, हाल के महीनों में विनिर्मित खाद्येतर उत्पादों के मूल्यों में देखा गया परिवर्तन दर्शाता है कि मूल्यों में वृद्धि होने वाली मदों की संख्या में गिरावट आई है जबकि मूल्यों में कमी आने वाली मदों की संख्या बढ़ी है। इसके बावजूद समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट नहीं आई क्योंकि कुछेक असंबद्ध मदों की कीमतों में होने वाले बदलाव समग्र स्थिति को प्रभावित करते हैं (चार्ट VI.8)।

चार्ट VI.8: खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन



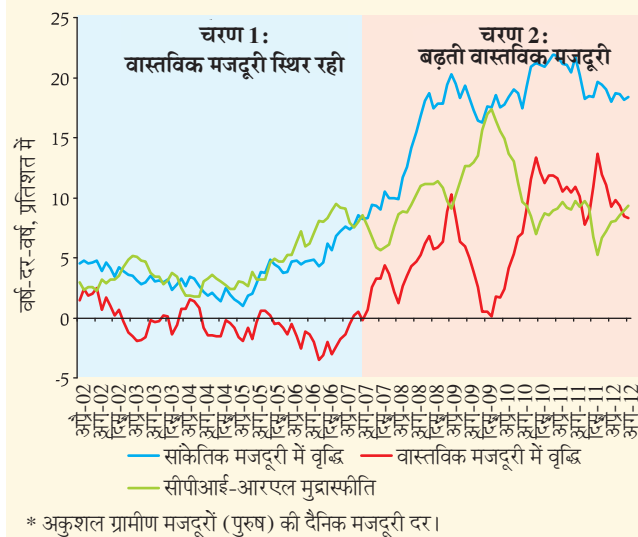
VI.22 जैसा कि एचएसबीसी मार्किट पर्चेजिंग मैनेजर्स इन्डेक्स से ज्ञात होता है, वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद निविष्टि लागत संबंधी दबाव बने हुए हैं। फर्म निविष्टि लागतों में हुई वृद्धि को उत्पादन मूल्यों में अंतरित करने के लिए बाध्य हो जाएं क्योंकि कंपनियों के लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय गिरावट आने के चलते इसे वहन करने की उनकी क्षमता में गिरावट आई है। इसके चलते वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति बनी रह सकती है।

मजदूरी संबंधी दबाव बने हुए हैं और ये मुद्रास्फीति को कम करने में बाधक हो सकते हैं

VI.23 खाद्य वस्तुओं की कीमतों एवं समग्र मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर रहने का एक मुख्य कारण ग्रामीण मजदूरी में, सांकेतिक तथा वास्तविक दोनों ही दृष्टि से, वृद्धि होना है। परंतु सांकेतिक बताते हैं कि ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि की दर अगस्त 2011 के लगभग 22 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से घटकर अगस्त 2012 में लगभग 18 प्रतिशत रह गई है। इसके कारण एवं हाल के महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में हुई बढ़ोतरी के चलते वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर अगस्त 2011 के 11 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2012 में लगभग 8 प्रतिशत रह गई है (चार्ट VI.9)। प्रमुख राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति तथा मजदूरी में हुई बढ़ोतरी में काफी बड़ा अंतर है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि मजदूरी व मूल्यों के आपसी संबंधों के राज्य विशिष्ट कारक होते हैं (चार्ट VI.10)।

VI.24 यहां तक कि संगठित क्षेत्र में भी यह देखा गया है कि 2011-12 के दौरान स्टाफ लागत में लगभग 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई

चार्ट VI.9: ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी* एवं मुद्रास्फीति



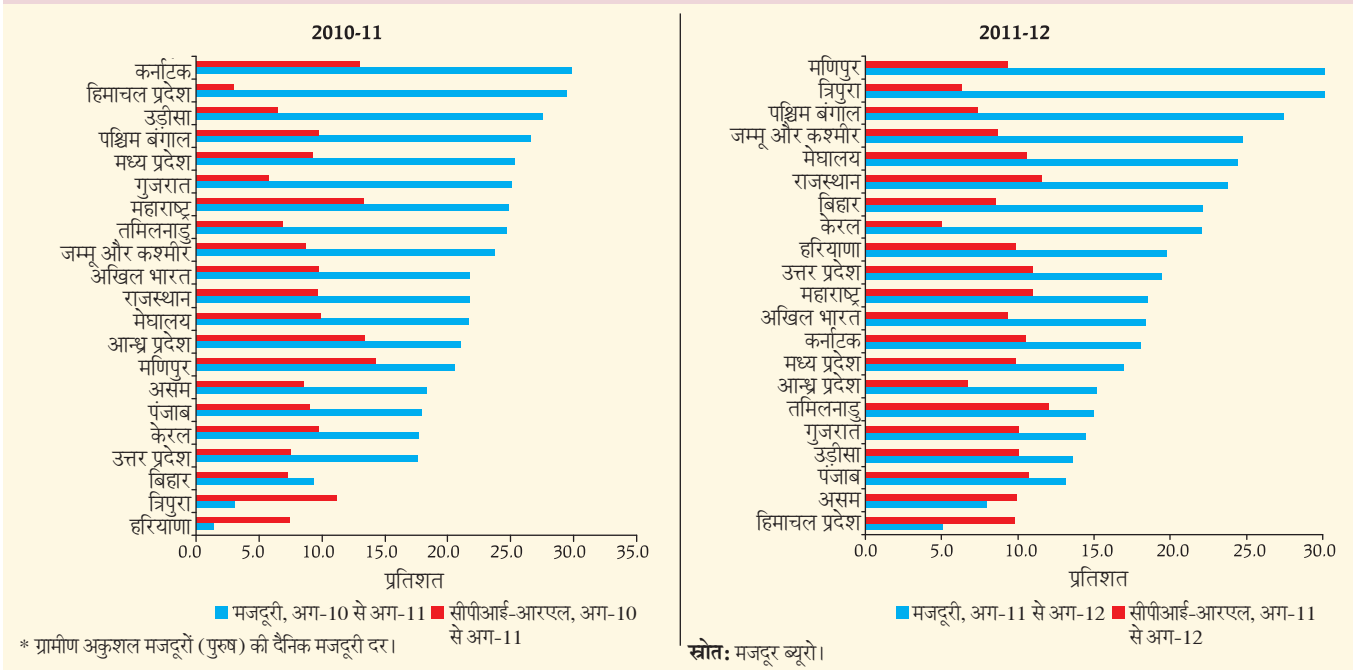
जो वेतन संबंधी लागत की उपस्थिति को दर्शाती है। स्टाफ की लागतों में पिछली तिमाहियों में कुछ गिरावट के आने के बाद स्टाफ की लागतों में हाल की तिमाही में फिर से वृद्धि हुई है (सारणी VI.3)।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य मुद्रास्फीति से अधिक बनी हुई है

VI.25 नए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त सीपीआई (ग्रामीण+शहरी)) के अनुसार मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही तथा सितंबर 2012 में इसकी दर 9.7 प्रतिशत थी। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन को अलग करने के बाद हाल के महीनों में इसमें कुछ गिरावट दिखाई दी है (सारणी VI.3)। परंतु नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें खाद्य वस्तुएं तथा ईंधन शामिल नहीं है, थोक मूल्य सूचकांक के तुलनीय घटकों से उच्चतर है। समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थ के समूह के योगदान में हाल के महीनों में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि सितंबर 2012 में इसमें मामूली गिरावट आई। इसके चलते मुद्रास्फीति के मूल घटकों में गिरावट के बावजूद समग्र मुद्रास्फीति उंची रही है (चार्ट VI.11)। हाल के महीनों में सीपीआई मुद्रास्फीति में ईंधन तथा बिजली एवं विविध मदों (जिसमें सेवाएं शामिल हैं) के योगदान में गिरावट आई है।

VI.26 उल्लेखनीय रूप से थोक मूल्य सूचकांक तथा नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति में कुछ उत्पाद समूहों जैसे, मसालों, फलों एवं सब्जियों तथा कपड़े व बेडिंग के मामलों में काफी अंतर पाया गया है। दोनों ही मुद्रास्फीति मापकों की समान मद समूहों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि ईंधन तथा

चार्ट VI.10: ग्रामीण मजदूरों (सीपी-आरएल) एवं ग्रामीण मजदूरी के सीपीआई में वृद्धि

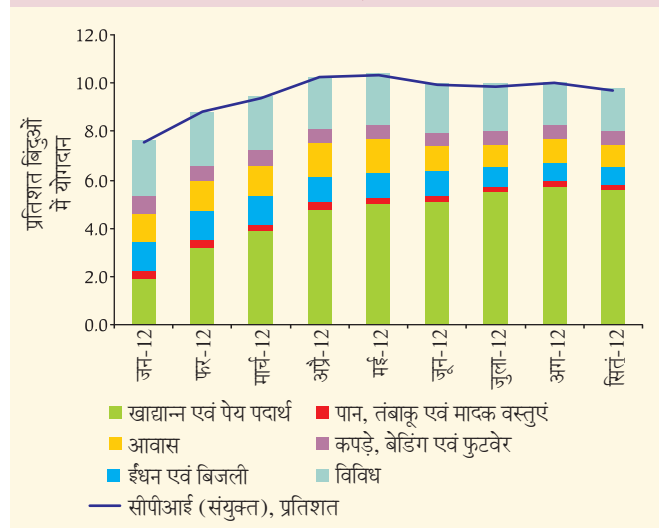


सारणी VI.3: थोक मूल्य सूचकांक एवं नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति

	खाद्यान्न		ईंधन		खाद्यान्न एवं ईंधन को छोड़कर		समग्र	
	डब्ल्यूपी आई	नया सीपी आई	डब्ल्यूपी आई	नया सीपी आई	डब्ल्यूपी आई	नया सीपी आई	डब्ल्यूपी आई	नया सीपी आई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भार	24.3	47.6	14.9	9.5	60.8	42.9	100	100
जन-12	1.5	3.9	17.0	13.0	7.5	10.6	7.2	7.5
फर-12	5.9	6.7	15.1	12.8	6.3	10.4	7.6	8.8
मार्च-12	8.7	8.1	12.8	11.8	5.8	10.2	7.7	9.4
अप्रै-12	9.3	10.1	12.1	11.2	5.4	10.2	7.5	10.3
मई-12	8.9	10.5	11.5	10.7	5.8	10.1	7.5	10.4
जून-12	9.1	10.8	12.1	10.3	5.6	8.9	7.6	9.9
जुला-12	9.0	11.6	8.4	7.3	6.5	8.5	7.5	9.9
अग-12	9.1	12.1	8.3	7.5	6.6	8.3	7.6	10.0
सित-12	8.5	11.7	11.9	7.3	6.3	8.2	7.8	9.7

बिजली को छोड़कर अधिकांश उत्पाद समूहों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक से अधिक था। इस अंतर का आंशिक कारण भारांकन की पद्धति में अंतर, क्षेत्र का कवरेज तथा बाजारों का कवरेज हो सकता है। इससे थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति के सामान्यतः उच्च रहने की बात स्पष्ट होती है, जो उच्चतर परिवहन तथा श्रमिक लागत एवं आपूर्ति की शृंखला की अड़चनों की वजह से है।

चार्ट VI.11: नये सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति में योगदान



मुद्रास्फीति का रुख असहज स्तर पर है; आपूर्ति संबंधी बेहतर उपाय तथा उत्पादकता में वृद्धि मध्यावधि में मूल्य स्थिरता के लिए जरूरी है

VI.27 वृद्धि दर में काफी गिरावट एवं वैश्विक मुद्रास्फीति का माहौल अनुकूल रहने के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति का निरंतर बना रहना अनूठी बात है। आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से, भारत की उच्च मुद्रास्फीति ईंधन की कीमतों का विलंब से समायोजन एवं ढांचागत कारकों की

भूमिका दर्शाती है। मांग पक्ष की दृष्टि से, उत्पादकता में वृद्धि की तुलना में वास्तविक मजदूरी में हुई वृद्धि तथा उच्च राजकोषीय घाटे ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों में बढ़ोतरी की है। अतः नीतिगत उपायों से मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट की स्थिति लायी जा सकती है ताकि ढांचागत बाधाओं को दूर किया जा सके। साथ ही उत्पादकता के स्तर में सुधार करके अर्थव्यवस्था में प्रति श्रमिक लागतों को कम करने की जरूरत है ताकि वास्तविक मजदूरी की दर को गैर-स्फीतिकारी तरीके से बढ़ाया जा सके।

VI.28 आगे, अपर्याप्त तथा असमान मानसून एवं वैश्विक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि ने खाद्य मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं जोड़ दी हैं। तेल के नियंत्रित मूल्यों में किये गये संशोधन से अल्पावधि

में कीमत का दबाव बढ़ सकता है, परंतु इससे समष्टि आर्थिक मूल तत्वों में सुधार लाने में मदद मिलेगी। यद्यपि 2011-12 की अंतिम तिमाही के दौरान विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट आयी, फिर भी यह उच्चतर स्तर पर रही क्योंकि निविष्टि लागतों के निरंतर दबावों, अंतरित प्रभावों तथा मजदूरी संबंधी उल्लेखनीय दबावों ने वृद्धि दर में आयी गिरावट के असर को संतुलित किया। अल्पावधि में मुद्रास्फीति लगभग वर्तमान स्तर पर बनी रह सकती है तथा इसमें उल्लेखनीय कमी तभी हो सकती है जब ढांचागत कारकों में सुधार हो। वृद्धि दर में आयी गिरावट तथा उत्पादन अंतर की ऋणात्मक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति का रुख चिंता का विषय बना हुआ है।